खबरों में रहे स्टॉक

ल्यूपिन

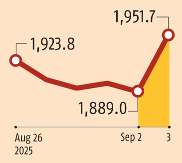

रिसपेरीडोन लॉन्ग-एक्टिंग इंजेक्शन के लिए मिली यूएसएफडीए की मंजूरी

₹ 1,889.0 पिछला बंद भाव
₹ 1,951.7 आज का बंद भाव
3.3 % ▲

नेटवेब टेक्नॉलजीज इंडिया

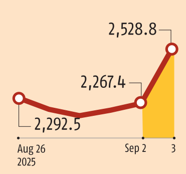

एनवीडिया ब्लैकवेल सर्वरों के लिए 1,734 करोड़ रुपये का ऑर्डर हासिल मिला

₹ 2,267.4 पिछला बंद भाव
₹ 2,528.8 आज का बंद भाव
11.5 % ▲

टीबीओ टेक

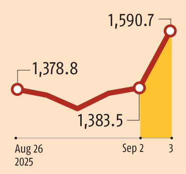

वैश्विक मौजूदगी बढ़ाने को 12.5 करोड़ डॉलर में खरीदी क्लासिक वेकेशन्स

₹ 1,383.5 पिछला बंद भाव
₹ 1,590.7 आज का बंद भाव
15.0 % ▲

एक्मे सोलर होल्डिंग्स

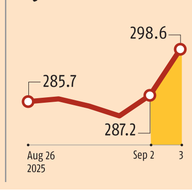

टाटा पावर से 50 मेगावॉट की एफडीआरई परियोजना हासिल की

₹ 287.2 पिछला बंद भाव
₹ 298.6 आज का बंद भाव
4.0 % ▲

मैन इंडस्ट्रीज इंडिया

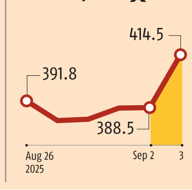

कोटेड पाइपों के लिए 1,700 करोड़ रुपये का नया निर्यात ऑर्डर मिला

₹ 388.5 पिछला बंद भाव
₹ 414.5 आज का बंद भाव
6.7 % ▲

संक्षेप में

पार्श्वनाथ डेवलपर्स को 347 करोड़ रु का घाटा

रियल एस्टेट कंपनी पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड को गत वित्त वर्ष 2024-25 में कम आय के कारण 347.27 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध घाटा हुआ। वित्त वर्ष 2023-24 में उसका शुद्ध घाटा 594.13 करोड़ रुपये था। कंपनी की वित्त वर्ष 2024-25 में कुल आय घटकर 303.45 करोड़ रुपये रह गई जो 2023-24 में 493.72 करोड़ रुपये थी। दिल्ली स्थित पार्श्वनाथ डेवलपर्स ने उत्तर भारत में कई आवासीय एवं वाणिज्यिक परियोजनाएं विकसित की हैं। *भाषा*

वेदांत के प्रस्ताव पर फैसला टला

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ओडिशा के रायगढ़ और कालाहांडी जिलों में सिजिमाली बॉक्साइट खदानों के लिए 700 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को हस्तांतरित करने के वेदांत लिमिटेड के प्रस्ताव पर फैसला टाल दिया है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, मंत्रालय ने सामुदायिक सहमति, प्रतिपूरक वनरोपण और पारिस्थितिक जोखिमों से जुड़े अनसुलझे मुद्दों का हवाला देते हुए यह फैसला टाल दिया। मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (एफएसी) की बैठक 25 अगस्त को हुई थी। एफएसी ने कहा कि ओडिशा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में ग्रामीणों एवं याचिकाकर्ताओं द्वारा ओडिशा उच्च न्यायालय के समक्ष उठाई गई चिंताओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। *भाषा*

कार्ल्सबर्ग का आईटी वैश्विक क्षमता केंद्र शुरू

बीयर बनाने वाली दुनिया की प्रमुख कंपनियों में से एक कार्ल्सबर्ग ग्रुप ने बुधवार को भारत में अपने पहले आईटी वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) शुरू किये जाने की घोषणा की। यह कदम भारत जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने और डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया को तेज करने की उसकी योजनाओं का हिस्सा है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह केंद्र कार्ल्सबर्ग की वैश्विक डिजिटल यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। *भाषा*

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
आपकी प्रगति का सच्चा साथी Good people to grow with
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
केंद्रीय कार्यालय: 763, अण्णा सालै, चेन्नै – 600 002

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आइओबी) निम्नलिखित के लिए बोली लगाने हेतु आमंत्रित करता है:

ब्रीच अटैक सिम्युलेशन व सतत स्वचालित रेड टीमिंग उपकरण की क्रय एवं परिचालन संबंधी प्रक्रिया हेतु।

सरकारी ई-मार्केट पोर्टल संदर्भ संख्या:- जीईएम/2025/बी/6633729 दिनांक 01.09.2025

पर्युक्त निविदा के लिए जीईएम दस्तावेज उल्लिखित वेबसाइटों पर www.iob.in एवं www.gem.gov.in उपलब्ध है, जहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा का विवरण और भविष्य में किए जाने वाले किसी भी संशोधन के लिए, उक्त वेबसाइट www.gem.gov.in का संदर्भ लेते रहें।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
निवेशक संबंध कक्ष
केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै–600002
फोन: 044–7172 9791, 2888 9360

सूचना

निविदा संदर्भ सं: GEM/2025/B/6642265 दिनांकित 03.09.2025

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, 01.11.2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक कंपनियों/आरटीए से प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित करता है। उपरोक्त निविदा संविदा दस्तावेज़ भी उपलब्ध है और इसे निम्नलिखित वेबसाइटों **www.iob.bank.in** और **www.gem.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।
निविदा संबंधी विवरण और भविष्य में किसी भी संशोधन, यदि कोई हो, के लिए बैंक की वेबसाइट **www.iob.bank.in** और **www.gem.gov.in** देखें।
बोली लगाने संबंधी दस्तावेज़ प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय **25.09.2025 को शाम 5.00 बजे** तक है।
स्थान: चेन्नै
दिनांक: 03.09.2025 उप महा प्रबंधक

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI
प्रधान कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी(अभिशासन एवं श्रेष्ठता) विभाग, स्टार हाउस -3, पीएनबी-बीओआई टावर, सी-29, जी ब्लॉक, 10वां तल, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई-400051.
ई-मेल: HOIT.G&E@bankofindia.co.in

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

संदर्भ संख्या: बीओआई : एचओ: आईटी: एनएसी : एएस: 1173 दिनांक 21.08.2025 के माध्यम से पार्ट कोडेड आरएफपी प्रक्रिया द्वारा घरेलू, एफसीबीएस एवं आरआरबी सेगमेंट के लिए 5 वर्षों हेतु एफसीबीएस के लिए हार्डवेयर, एएमसी का नवीनीकरण एवं अरूबा के क्लियरपास नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी) सॉल्यूशन के एफएमएस सपोर्ट के लिए।

GeM Bid No. GEM/2025/B/6590573 Dt. 21.08.2025

उपर्युक्त आरएफपी "निविदा" अनुभाग एवं GeM पोर्टल के अंतर्गत बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर उपलब्ध है।

इसके बाद यदि कोई परिवर्तन होगा, तो उसे बैंक की वेबसाइट एवं GeM पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: 11.09.2025

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of india Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)
स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर
पंजीकृत कार्यालय : आईएफसीआई टॉवर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली – 110 019
फोन : 41732000 फैक्स: 011–26230201
वेबसाईट : www.ifciltd.com
सीआईएन : L74899DL1993GOI053677

निविदा संख्या: आईएफसीआई/एचओ/सीएमएल-आर/06/2025 - 26, दिनांक 04/09/2025
स्विस चैलेंज पद्धति के तहत आईएफसीआई द्वारा एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड के ऋण खाते का असाइनमेंट

आईएफसीआई लिमिटेड 100% नकद आधार पर स्विस चैलेंज प्रोसेस के माध्यम से निम्नलिखित एक्सपोजर के असाइनमेंट के लिए काउंटर बोलियां आमंत्रित करता है:
(करोड़ रुपये में)

खाते का नाम	बकाया राशि (31/07/2025 तक)	आरक्षित मूल्य	बिक्री की शर्तें
एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड (एसीसीआईएल)	869.27	50.00	100% नकद आधार पर

निविदा दस्तावेज़ तथा विस्तृत निबंधन व शर्तें हमारी वेबसाइट **(http://www.ifciltd.com) Tenders→Sale of Assets→NPA** के तहत अपलोड कर दिया गया है। ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि 11/09/2025 सांय 5:00 बजे तक है। ई–नीलामी 26/09/2025 तारीख को होगी।
निविदा से सम्बन्धित सभी शुद्धि–पत्र/परिशिष्ट/आशोधन/समय वृद्धि की सूचना/स्पष्टीकरण आदि, यदि कोई हो, को केवल **(http://www.ifciltd.com)** वेबसाइट पर ही डाला जाएगा।
नोट: आईएफसीआई के पास सभी अथवा किसी प्रस्ताव को बिना कोई कारण बताए, चाहे वह कुछ भी क्यों न हो, पूर्णतः अथवा अंशतः अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04/09/2025
हस्ताक्षर/–
उप महाप्रबन्धक (सीएमएल एंड आर)

चैलेंज नीलामी में शामिल होंगे जयप्रकाश एसो. के बोलीदाता

रुचिका चित्रवंशी और देव चटर्जी
नई दिल्ली/मुंबई, 3 सितंबर

जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के ऋणदाताओं ने सभी समाधान आवेदकों से इस संकटग्रस्त कंपनी के लिए शुक्रवार को चैलेंज नीलामी में भाग लेने को कहा है। इसके लिए न्यूनतम बोली राशि 12,000 करोड़ रुपये रखी गई है। इससे जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है। इसकी गणना शुद्ध वर्तमान मूल्य के आधार पर की जाएगी।

यह चैलेंज नीलामी ईमेल के जरिये होगी, जहां बोली के हर दौर के बाद ऋणदाता इसमें शामिल कंपनियों से अपनी बोली कम से कम 250 करोड़ रुपये बढ़ाने के लिए कहेंगे। सूत्रों ने बताया कि ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) ने आवेदकों से यह प्रतिबद्धता भी मांगी है कि अगर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) भूमि का मामला उनके पक्ष में सुलझ जाता है, तो क्या वे ऋणदाताओं को अतिरिक्त राशि का भुगतान करेंगे।

जेएएल के लिए ये बोलियां ग्रेटर नोएडा में जेएएल की 1,000 हेक्टेयर की स्पोर्ट्स सिटी परियोजना से जुड़े कानूनी विवाद के परिणाम पर निर्भर है।

लेनदारों ने की तैयारी

- समाधान आवेदक इस संकटग्रस्त कंपनी के लिए शुक्रवार को लेंगे नीलामी में भाग
- इसके लिए न्यूनतम बोली राशि 12,000 करोड़ रुपये रखी गई है
- नीलामी ईमेल के जरिये होगी, हर दौर के बाद 250 करोड़ रुपये बढ़ाने होंगे

मार्च में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस परियोजना के लिए भूमि आवंटन रद्द करने के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के फैसले को बरकरार रखा था। अब मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

अदाणी समूह, डालमिया समूह, वेदांत समूह, जिंदल स्टील ऐंड पावर (जेएसपीएल) और पीएनसी इन्फ्राटेक वे पांच कंपनियां हैं, जो ऋणग्रस्त जेएएल की दौड़ में हैं। जेएएल की परिसंपत्तियों में सीमेंट, रियल एस्टेट, बुनियादी ढांचा, आतिथ्य-सत्कार तथा जेपी ग्रीन्स, विश टाउन और आगामी जेवर हवाई अड्डे के निकट इंटरनैशनल स्पोर्ट्स सिटी जैसी प्रमुख विकास परियोजनाएं शामिल हैं।

घटनाक्रम के करीबी सूत्र अनुसार, 'बोलीदाताओं को हर दौर से पहले अपनी बोली की समीक्षा और चर्चा के लिए एक घंटे का वक्त मिलेगा तथा ऋणदाता फॉर्मूले पर आधारित एक तरीके के जरिये प्रत्येक दौर की बोलियों की समीक्षा के लिए आधे घंटे का वक्त लेंगे।' सूत्र ने कहा कि अगर लगातार दो दौर में सर्वाधिक बोली समान ही रहती है तो चैलेंज प्रक्रिया रोक दी जाएगी और ऋणदाता सभी समाधान आवेदकों से धन के स्रोत के साथ अपनी संशोधित योजना की प्रति जमा करने को कहेंगे।

सूत्र ने कहा, 'संशोधित योजनाएं ऋणदाताओं को यीडा की भूमि के लिए निपटारे आदि जैसी एनपीवी के अलावा प्रस्तावित राशि की जानकारी प्रदान करेंगी।'

जेएएल के खिलाफ लेनदारों द्वारा स्वीकार किए गए कुल दावे 59,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बैठते हैं।

इन पांच में से दो बोलीदाताओं - अदाणी समूह और डालमिया भारत ने अपने अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की मंजूरी हासिल कर ली है। अन्य दो - पीएनसी इन्फ्राटेक और जिंदल पावर फिलहाल समीक्षाधीन हैं।

वेदांत समूह ने अभी तक अपनी समाधान योजना के लिए सीसीआई की मंजूरी के लिए आवेदन नहीं किया है।

यूसीपीएमपीडी का करना होगा सख्ती से अनुपालन

नैतिक संहिता से बढ़ेगी फार्मा फर्मों की लागत

सोहिनी दास
मुंबई, 3 सितंबर

दवा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र की भारतीय कंपनियों का कहना है कि चिकित्सा उपकरणों में मार्केटिंग प्रैक्टिसेज के लिए समान संहिता 2024 (यूसीपीएमपीडी) का सख्ती से अनुपालन कंपनियों को अनैतिक व्यापार और विपणन के तौर-तरीकों को रोकने का काम करेगा। लेकिन इससे अनुपालन की लागत में इजाफा होगा। हालांकि मार्केटिंग खर्च से संबंधित डिस्क्लोजर जमा करने की समयसीमा को 30 सितंबर तक और बढ़ा दिया गया है।

कंपनियों को वित्त वर्ष की समाप्ति के दो महीने के भीतर मार्केटिंग से जुड़े खर्च की अनिवार्य तौर पर वार्षिक घोषणाएं करनी होती हैं। लेकिन इस वर्ष यह समयसीमा दो बार बढ़ाई जा चुकी है और अब इसे 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है। पहले ये घोषणाएं 30 जून तक जमा किए जाने की उम्मीद थी जिन्हें दो बार बढ़ाकर पहले 31 जुलाई और फिर 31 अगस्त कर दिया गया।

इस शपथपत्र पर कंपनी के कार्यकारी प्रमुख के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो मार्केटिंग की कार्यप्रणाली की संहिता के अनुपालन का आश्वासन देता हो। इस पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कंपनी का प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्य अधिकारी (सीईओ) हो सकता है।

इस संहिता में मूल्यांकन वाले मुफ्त नमूनों की सीमा को घरेलू बिक्री के 2 प्रतिशत तक तय किया गया है और अगर नमूने आंतरिक स्तर पर बनाए गए हैं तो उनका मूल्यांकन स्टॉकिस्ट मूल्य पर किया जाएगा और अगर बाहर से लिए गए हैं तो यह क्रय मूल्य पर दर्ज किया जाएगा। कंपनियों को नमूनों, सीएमई कार्यक्रमों, कार्यक्रमों के प्रायोजनों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की अंतरराष्ट्रीय यात्राओं, आवास और आतिथ्य-सत्कार के लिए आवश्यक पूर्व मंजूरियों पर खर्च का भी खुलासा नए निर्धारित अनुलग्नक प्रारूप में करना होगा।

हितों के टकराव को खत्म करने के उद्देश्य से इस संशोधित ढांचे में स्वास्थ्य सेवा के पेशेवरों और उनके परिवारों को उपहार, नकद अनुदान और व्यक्तिगत यात्रा या आतिथ्य-सत्कार के लाभों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उद्योग संघों को डिस्क्लोजर का डेटा पांच वर्षों तक संभालकर रखना होगा। इसके उल्लंघन करने पर कड़े दंड का भी प्रावधान है। हालांकि विश्लेषकों ने बताया कि इससे कंपनियों की अनुपालन लागत बढ़ जाएगी।

दवा निर्माण प्रक्रिया में विलंब घटाने की तैयारी

सोहिनी दास
मुंबई, 3 सितंबर

देश में दवा विकास और मंजूरी की समय-सीमा कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय दवा नियामक न्यू ड्रग्स ऐंड क्लीनिकल ट्रायल्स (एनडीसीटी) नियम, 2019 में संशोधन की योजना बना रहा है। परीक्षण लाइसेंस आवेदनों के लिए लगने वाला प्रोसेसिंग से संबंधित समूचा समय 90 दिन से 45 दिन किया जा सकता है। वैश्विक चिकित्स क ीय परीक्षणों में भारत की हिस्सेदारी लगभग 8 प्रतिशत है। कई फार्मा कंपनियां नियामकीय बाधाओं के कारण अपने प्रारंभिक चरण के परीक्षण विदेशों में कराती हैं। 3 सितंबर की अधिसूचना में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधनों पर सार्वजनिक सुझाव मांगे हैं। इनका उद्देश्य परीक्षण लाइसेंस प्राप्त करने और बायोएवेबिलिटी/बायोइक्विलेंस (बीए/बीई) अध्ययनों से संबंधित आवेदन पेश करने की शर्तों और प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।

इन बदलावों से कंपनियों को खास चिकित्सकीय परीक्षण करने और बगैर लाइसेंस के इन परीक्षणों के लिए जरूरी दवाएं तैयार करने में मदद मिलेगी। हालांकि ये गतिविधियां सिर्फ नियामक को सूचित करने के बाद शुरू की जा सकती हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य बीए/बीई अध्ययनों की शीघ्र शुरुआत सुनिश्चित करना भी है।

हालांकि, यह रियायत केवल उन ओरल फॉर्मूलेशनों के मामले में लागू होगी जिन्हें पहले से ही यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा जैसे सख्त नियामकीय प्रणालियों वाले देशों में लागू किया जा चुका है।

प्रस्तावित प्रमुख संशोधनों में से एक परीक्षण लाइसेंस जारी करने की मौजूदा प्रणाली को अधिसूचना/सूचना प्रणाली में परिवर्तित करना भी शामिल है। आवेदक औषधि नियामक से लाइसेंस लेने के लिए प्रतीक्षा से बच सकते हैं और वे केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सूचित करने के बाद अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। अधिक जोखिम वाली दवाओं की एक छोटी श्रेणी को अभी भी यह मंजूरी लेनी होगी। हालांकि संशोधन के अनुसार परीक्षण लाइसेंस आवेदनों के लिए कुल वैधानिक प्रक्रिया का समय 90 दिन से घटाकर 45 दिन किया जा सकता है।

मंत्रालय का मानना है कि प्रस्तावित संशोधनों से केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) को अपने मानव संसाधन का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी क्योंकि लाइसेंस आवेदनों की संख्या में संभावित रूप से 50 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। बीए/बीई अध्ययन, परीक्षण आदि की शीघ्र शुरुआत से दवा विकास और अनुमोदन प्रक्रियाओं में लगने वाला समय घटेगा।

मारुति सुजूकी के लिए ...

'छोटी कारें आधार एसयूवी भी दमदार'

दीपक पटेल
नई दिल्ली, 3 सितंबर

मारुति सुजूकी ने बुधवार को अपने नई मिड-साइज एसयूवी विक्टोरिस को पेश किया। यह तेजी से लोकप्रिय हो रही इस श्रेणी में कंपनी की दूसरी पेशकश है। मारुति सुजूकी के एमडी और सीईओ हिसाशी ताकेउची का कहना है कि कंपनी अपनी बाजार हिस्सेदारी को मजबूत करने, निर्यात बढ़ाने और एसयूवी की बढ़ती मांग के साथ छोटी कारों पर अपने लंबे समय से ध्यान देने के प्रयासों को संतुलित करने की कोशिश कर रही है।

4 से 4.5 मीटर लंबे एसयूवी को मिड-साइज एसयूवी माना जाता है।

सुजूकी जापान से भारत में अधिक निर्यात उत्पादन स्थानांतरित कर रही है, क्योंकि कंपनी की वैश्विक रणनीति में भारत का महत्व लगातार बढ़ रहा है।

नई विक्टोरिस को दुनिया भर के लगभग 100 बाजारों में भेजने की योजना है, जिससे एक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की महत्ता का पता चलता है। ताकेउची ने एसयूवी की पेशकश के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा, 'निर्यात पर हमेशा विचार किया जाता है। सुजूकी जापान अपने निर्यात बाजार का अधिक से अधिक हिस्सा जापान से भारत की ओर स्थानांतरित कर रहा है। भारत से, हम बेहद प्रतिस्पर्धी कीमतों पर और एक मजबूत, टिकाऊ वाहन का निर्यात कर सकते हैं।'

हिसाशी ताकेउची

मारुति सुजूकी के लिए निर्यात का आंकड़ा घरेलू बिक्री की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी ने 2024-25 में 330,000 वाहनों का निर्यात किया और वर्ष 2030-31 तक इसे दोगुना से ज्यादा कर 750,000 वाहन पर पहुंचाने की योजना है। ताकेउची ने इस बात पर जोर दिया कि एसयूवी में सफलता, यात्री वाहनों में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी को पुनः प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो मौजूदा समय में लगभग 40 प्रतिशत है, जबकि पहले यह 50 प्रतिशत से अधिक थी।

उन्होंने कहा, 'अब एसयूवी की कुल बाजार हिस्सेदारी 55 प्रतिशत है, इसलिए इस सेगमेंट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।' मारुति सुजूकी की कुल बिक्री में एसयूवी की हिस्सेदारी 28 प्रतिशत है, जो वर्ष 2020-21 के 8.9 प्रतिशत से लगभग तीन गुना ज्यादा है। लगभग 1,240 करोड़ रुपये के निवेश के साथ विक्टोरिस का निर्माण कंपनी के खरखौदा संयंत्र में किया जाएगा।

जियो 9वीं वर्षगांठ पर देगी मुफ्त असीमित डेटा

देश की प्रमुख दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने अपनी 9वीं वर्षगांठ के मौके पर सभी ग्राहकों के लिए फ्री असीमित डेटा पेशकश की शुरुआत की है। कंपनी ने बुधवार को बताया कि यह पेशकश मौजूदा प्लान के आधार पर अलग-अलग अवधि के लिए उपलब्ध होगी। एक आधिकारिक बयान में कंपनी ने कहा कि 349 रुपये या उससे अधिक मूल्य वाले प्लान के ग्राहकों को 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक एक महीने के लिए असीमित डेटा मिलेगा। इसके साथ ही इस पेशकश में मनोरंजन और अन्य ऐप की सब्सक्रिप्शन भी शामिल होगी। वर्तमान में जियो केवल 349 रुपये या उससे अधिक कीमत वाले प्लान वाले 5जी स्मार्टफोन ग्राहकों को अनलिमिटेड 5जी डेटा प्रदान करती है।

रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने इस अवसर पर कहा, 'जियो की 9वीं वर्षगांठ पर मुझे गर्व है कि 50 करोड़ से अधिक भारतीयों ने हम पर भरोसा जताया है। एक ही देश में इस पैमाने तक पहुंचना दर्शाता है कि जियो रोजमर्रा की जिंदगी का कितना गहरा हिस्सा बन चुकी है। मैं इस मील के पत्थर को संभव बनाने के लिए हर एक जियो उपयोगकर्ता का व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं।' इसके अलावा, जियो ने उन ग्राहकों के लिए भी अच्छी खबर दी है जिन्होंने लगातार 12 महीने 349 रुपये के प्लान का रिचार्ज किया है। ऐसे ग्राहकों को 13वें महीने की सेवा मुफ्त दी जाएगी।

प्रवर्तक समूह की कंपनियों ने जियो फाइनैंशियल में 3,956 करोड़ रुपये की पूंजी डाली

जियो फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड (जेएफएसएल) ने बुधवार को कहा कि प्रवर्तक समूह की इकाइयों ने कंपनी के विस्तार के लिए 3,956 करोड़ रुपये की पूंजी डाली है। जेएफएसएल ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी के निदेशक मंडल ने प्रवर्तक समूह के सदस्यों - सिक्का पोर्ट्स ऐंड टर्मिनल्स लिमिटेड और जामनगर यूटिलिटीज ऐंड पावर प्राइवेट लिमिटेड को 316.50 रुपये प्रति वारंट की दर से 50 करोड़ वारंट आवंटित किए हैं। इससे कुल मिलाकर कंपनी को 3,956.25 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। दोनों कंपनियों को 316.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से 25-25 करोड़ वारंट आवंटित किए गए हैं। *भाषा*

एमेजॉन फ्रेश क्षेत्रीय खान-पान को कर रही कैश

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 3 सितंबर

देश में त्योहारी खरीदारी के आकर्षक सीजन में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए एमेजॉन फ्रेश क्षेत्रीय विशिष्टताओं और तेज डिलिवरी की रफ्तार पर जोर दे रही है। इसकी वजह यह है कि ई-कॉमर्स क्षेत्र की इस दिग्गज को स्विगी इंस्टामार्ट, ब्लिंकइट और जेप्टो जैसे क्विक-कॉमर्स प्लेटफार्मों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।

कंपनी ने प्रामाणिक क्षेत्रीय उत्पादों वाले एक 'लोकल डिलाइट स्टोर' की शुरुआत की है और देश भर के 11,000 से ज्यादा किसानों के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है। कंपनी 'एमेजॉन नाउ' की भी प्रायोगिक शुरुआत कर रही है। यह चुनिंदा क्षेत्रों में रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अति-तीव्र डिलिवरी वाली सेवा है।

एमेजॉन फ्रेश के निदेशक श्रीकांत श्री राम ने कहा, 'त्योहारी सीजन हमारे कृषि साझेदारों के लिए अहम समय होता है, क्योंकि इससे उन्हें देश भर के लाखों ग्राहकों तक पहुंचने का अवसर मिलता है।' उन्होंने कहा, 'सीधे किसानों से उत्पाद लेकर हम उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करते हैं।' श्री राम ने कहा कि छोटे कारोबारियों के साथ सहयोग से ग्राहकों को प्रामाणिक और क्षेत्रीय रूप से पसंदीदा उत्पादों तक पहुंच सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा, 'चाहे वह मध्य प्रदेश का ताजा पोहा हो, कश्मीर का केसर या गुजरात का घी।'

क्विक-कॉमर्स में घमासान का अंजाम

- त्योहारी खरीदारी की प्रतिस्पर्धा बढ़ने से ई-कॉमर्स दिग्गज ने की 11,000 किसानों के साथ साझेदारी
- कंपनी ने की है प्रामाणिक क्षेत्रीय उत्पादों वाले 'लोकल डिलाइट स्टोर' की शुरुआत, 'एमेजॉन नाउ' की भी प्रायोगिक शुरुआत कर रही कंपनी

आपूर्ति श्रृंखला के तहत तकनीक की बदौलत एमेजॉन फ्रेश के गुणवत्ता का वादा पूरा करने में मदद मिल रही है। ताजगी बरकरार रखने के लिए ठंडी वस्तुओं को जेल पैड वाले इंसुलेटेड बैग में पैक किया जाता है। यह तुड़ाई से लेकर डिलिवरी तक पांच घंटे के दौरान तापमान को -5 डिग्री सेंटीग्रेड से शून्य डिग्री सेंटीग्रेड के बीच बनाए रखते हैं जबकि फ्रोजन उत्पादों को -24 डिग्री सेंटीग्रेड से -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। तकनीक से संचालित यह प्रक्रिया कंपनी को ताजे फलों, सब्जियों और किराने की विस्तृत श्रृंखला को ग्राहकों के घर तक उनके चुने हुए वक्त पर पहुंचाने में सक्षम बनाती है।

श्री राम ने कहा, 'हम ताजे फल और सब्जियों से लेकर पैकेट बंद खाद्य, दूध और ब्रेड जैसे डेयरी उत्पाद, फ्रोजन उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन, शिशु देखभाल संबंधी जरूरी सामान, पर्सनल केयर उत्पाद और पालतू जानवरों की जरूरतों का सामान सब कुछ दो घंटे में उपलब्ध कराते हैं।'

दिल्ली संस्करण : बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड, डी-210-211, सेक्टर-63 नोएडा-201301 उ.प्र. और डी.बी कॉर्प लिमिटेड 10, जेएलएन मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर - 302015 से मुद्रित एवं नेहरू हाउस, 4, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित
संपादक : कैलाश नौटियाल, पीआरजीआई रजिस्ट्रेशन नं. DELHIN/2008/27804 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 011-23720202/23762742
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्स बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013 ईमेल.. subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं